





## शहर &gt;&gt; अपडेट

## लाभुकों के बीच बकरियों का वितरण

रांची: मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत कांके प्रखंड कार्यालय में छह लाभुकों के बीच बकरी और बकरा का वितरण किया गया। मौके पर प्रमुख सोमनाथ मुंडा और प्रखंड पशु पालन पदाधिकारी डॉ सुदीपा बरया के हाथों संजय महतो, दिलीप उरांव, सुषमा तिर्की, संजु देवी, आशा देवी, और विशाल उरांव को 5-5 बकरी दिया गया। मौके पर प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉ सुदीपा बरया ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत कांके प्रखंड पशुपालन विभाग की ओर से बकरी और बकरा का वितरण लगातार किया जा रहा है इसी कड़ी में मंगलवार को भी कुछ लाभुकों के बीच में वितरण किया गया है इसका उद्देश्य है कि लोगों के पास स्वरोजगार हो और अपने पैरों पर खड़ा हो।

## चेतावनी

कृषि विभाग में करप्शन और भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी देने को

## 27 अप्रैल को कृषि निदेशालय का घेराव करेंगे किसान

## राष्ट्रीय खबर

रांची: झारखंड किसान महासभा ने कृषि निदेशालय घेरने की योजना बनाई है। इसके लिए पिछले कई दिनों से महासभा के स्तर से अलग अलग क्षेत्रों में किसानों से संपर्क साधे जा रहे हैं। राजू कुमार महतो (अध्यक्ष, झारखंड किसान महासभा) ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे सभी 27 अप्रैल को रांची में जुटें। निदेशालय घेराव के जरिये अपना आक्रोश जाहिर करें। कहा है कि कृषि विभाग में व्याप्त करप्शन और भ्रष्ट आचरण में दूबे अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगर



अब समय रहते आवाज बुलंद नहीं की गई तो आनेवाली पीढ़ियों के सामने और मुश्किल स्थिति

सामने आने वाली है। किसानों का भविष्य अंधकारमय होने का खतरा बना रहेगा। राजू महतो के

मुताबिक निदेशालय घेराव चुनावी रैली नहीं है। अपने अपने खर्च पर ही हक और अधिकार के

## न्यूज फटाफट

**पानी की कमी से परेशान हैं रिस्स के मरीज**  
रांची: झारखंड से सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिस्स में पीने के पानी की घोर कमी है। इस भीषण गर्मी में मरीजों को बाहर से पीने का पानी खरीदना पड़ता है। हालात यह हैं कि पांच रुपए की पर्वी पर रिस्स में मरीजों को चिकित्सीय सलाह तो मिल जाता है, लेकिन उसी मरीज को प्यास बुझाने के लिए 50 से 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दरअसल, रिस्स के पुराने बिल्डिंग में मरीजों को पीने का पानी मिल सके, इसके लिए वाटर कूलर तो जरूर लगा दिया गया। लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में वाटर कूलर शोभा बनकर रह गया है। इधर, ओल्ड इमरजेंसी (बरियातू टीओपी) के पास पांच रुपए प्रति लीटर की दर से पानी बेचा जाता है। वहीं रिस्स के पार्किंग स्थल के पास भी पांच रुपए लीटर पानी बेचा जा रहा है, जहां लोग पानी खरीदने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। इस चिलचिलाती धूप में मरीजों को वाई से बाहर पानी खरीदने के लिए आना पड़ता है, तब जाकर प्यास बुझती है। ओपीडी के पास तीन वाटर कूलर जरूर नजर आया, लेकिन इनमें से दो मशीनें बंद थीं। जबकि तीसरी मशीन के दो नल से पानी नहीं आता है। एक नल से बूंद-बूंद पानी निकल रहा था। 1 लीटर पानी भरने के लिए कम से कम 10 मिनट इंतजार करना पड़ता है। वहीं ओपीडी में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या सैकड़ों में होती है और उन्हें चिकित्सीय सलाह लेने में करीब 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में इस भीषण गर्मी में मरीजों को प्यास बुझाने के लिए बाजार से पीने का पानी खरीदने की मजबूरी हो जाती है।

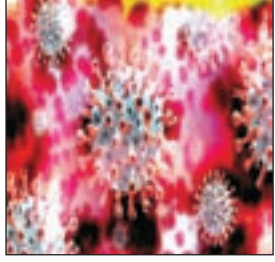
## बीएयू में विभागवार रिस्स एंड बजट कमिटी की बैठक

रांची: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अधीनस्थ कृषि, वानिकी एवं पशुचिकित्सा क्षेत्र के खरीफ अनुसंधान कार्यक्रमों का विभागवार रिस्स एंड बजट कमिटी की बैठक मंगलवार को शुरू हुआ। बीएयू के निदेशालय अनुसंधान के निदेश एवं मार्गदर्शन में विवि अधीन कार्यरत तीनों संकायों के विभिन्न विभागों एवं तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों में इस बैठक का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत कृषि संकाय अधीन कार्यरत मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से हुई। बैठक की अध्यक्षता निदेशक अनुसंधान डॉ पीके सिंह ने की। संबोधन में डॉ पीके सिंह ने गुणवत्ता युक्त एवं स्थानीय कृषि परिस्थितिकी तथा स्थानीय किसानों की मांग आधारित तकनीकी विकास पर जोर दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों को जनजातीय उपपरियोजना के शोध कार्यक्रम में पारदर्शिता रखने, विस्तृत प्रतिवेदन एवं सफल कहानी को संकलित करने का निर्देश दिया। बैठक में अध्यक्ष (मृदा विज्ञान) एवं डीन एग्रीकल्चर डॉ डीके शाही ने मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में चलाया जा रहे अनुसंधान कार्यक्रमों, उपलब्धियों एवं नये शोध कार्यक्रमों का सार प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आगामी खरीफ, 2023 में इफको के सौजन्य से सुपर नैनो यूरिया पर शोध कार्यक्रम शुरू होगा। आगामी खरीफ मौसम के लिए विभाग गुणवत्तायुक्त जैव उर्वरकों का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के अग्रिम मांग पत्र के अनुरूप जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जायेगा। ईच्छुक किसान भी विभाग से जैव उर्वरकों का क्रय कर सकते हैं। उन्होंने विभाग में स्वतंत्र सिंचाई जल जॉंच युनिट के स्थापना की आवश्यकता बताया। बैठक में विभाग के वैज्ञानिकों ने राज्य योजना अधीन स्थाई खाद प्रयोग (1956 से), साइल माइक्रोबायोलॉजी, मृदा एवं जल जॉंच तथा जैव उर्वरक उत्पादन एवं शोध, आईसीएआर योजना के अधीन दीर्घकालीन उर्वरक प्रयोग (1971 से), एसटीसीआर एवं माइक्रो एवं सेकेंडरी न्यूट्रीएन्ट प्रयोग, एडहोक योजना अधीन नैनो डीएपी प्रयोग के परिणाम एवं योजनाधीन आगामी खरीफ, 2023 के भावी शोध कार्यक्रमों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

## सक्रिय मरीजों की संख्या 197 हुई

## राष्ट्रीय खबर

रांची: झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में राज्य भर में 43 नये मरीज मिले हैं। वहीं रांची में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ रांची में संक्रमित मरीज का आंकड़ा बढ़कर 69 पर पहुंच गया है। वहीं राज्य भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 197 हो गयी है। हालांकि 28 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जिलावार संक्रमितों की संख्या बोकारो में 3, देवघर में 16, पूर्वी सिंहभूम में 44, गढ़वा में 4, गिरिडीह में 5,



गोड्डा में 1, गुमला में 10, हजारीबाग में 7, खूंटी में 2, कोडरमा में 6, लातेहार में 6, लोहरदगा में 8, पाकुड़ में 2, पलामू में 3, रामगढ़ में 6, रांची में 69 और पश्चिमी सिंहभूम में सक्रिय मरीजों की संख्या 5 है।

सोमवार रात 12 बजे के करीब

## कांके-राजभवन 33 केवी यूजी लाइन हुआ ब्रेक



## राष्ट्रीय खबर

रांची: इस भीषण गर्मी में रांची की एक लाख से अधिक आबादी बिना बिजली के 18 घंटे बिलबिलाती रही। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोड शेडिंग के तहत बिजली देने का दावा करने के बावजूद 18 घंटे में 18 मिनट भी बिजली नहीं रही। पावर कट से न केवल बिजली संकट उत्पन्न हो गया है, बल्कि पानी की समस्या से

भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। न्यू कैपिटल डिजिटल इंजीनियरिंग दिन से ही बिजली सामान्य होने का दावा करते रहे। मगर सामान्य नहीं हो पायी। देर शाम बिजली सामान्य होने का दावा किया जा रहा है राजभवन सबस्टेशन अंतर्गत रातू रोड फीडर, आर्यपुरी, इंद्रपुरी, रेडियो स्टेशन इलाका, मेट्रो गली, न्यू मधुकम फीडर, सर्किट हाउस फीडर, पहाड़ी फीडर पूरी तरह से प्रभावित रही

## 8 सदस्यों के भरोसे चल रहा जैक



रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) का हाल काफी बुरा है। जैक में अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्यों के कुल 19 स्वीकृत हैं। लेकिन वर्तमान यहाँ सिर्फ 8 सदस्य कार्यरत हैं। 11 पद खाली पड़े हैं। ऐसे हालात जनवरी 2020 से ही हैं। ऐसे में जैक बोर्ड में कार्यरत 8 सदस्य केवल अनिवार्य निर्णय ले रहे हैं। लेकिन 11 पद खाली होने से कई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जैक में सदस्यों के पद को भरने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दो बार विज्ञापन जारी किया, लेकिन सदस्यों का चयन नहीं हो सका। किसी न किसी कारण से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं पायी है। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में जिनका 15 वर्ष का अनुभव हो, वही जैक के सदस्य बन सकते हैं।

हंगामा &gt; कुलपति उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं

## रांची विश्वविद्यालय में दो सप्तिहडियरी पेपर की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा

## राष्ट्रीय खबर

रांची: रांची विश्वविद्यालय से सत्र 2017-20 और 2018-21 में स्नातक कर चुके विद्यार्थियों ने मंगलवार को दो सप्तिहडियरी पेपर की मांग को लेकर विवि मुख्यालय में हंगामा किया। अलग-अलग कॉलेजों के छात्रों ने विश्वविद्यालय कैम्पस में जमकर नारेबाजी की। इनका कहना था कि कुलपति उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। हंगामे के बीच कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा ने छात्रों को समझाया। एक घंटे में परीक्षा लेने का नोटिस जारी



करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद छात्र शांत हुए। हालांकि नोटिस जारी होने के इंतजार में

विद्यार्थी देर तक वहीं जमे रहे। रांची विश्वविद्यालय से सत्र 2017-20 और 2018-21 में

ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों को सप्तिहडियरी के तौर पर एक ही पेपर दिया गया था। इन दोनों सत्रों में पास करनेवाले जिन विद्यार्थियों ने बीएड की पढ़ाई की है, वे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि शिक्षक नियुक्ति में दो सप्तिहडियरी पेपर मांगता है। इस समस्या को लेकर विद्यार्थी पिछले चार महीने से विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं। कुलपति ने पहले भी आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक इसका हल नहीं निकाला गया है, जिससे विद्यार्थियों में रोष है।

# कोरोना से बचाव जरूरी

कोरोना वायरस के नये वेरियंट के लक्षण

1. जोड़ों में दर्द
2. सरदर्द
3. गरदन के पीछे दर्द
4. पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द
5. न्यूमोनिया
6. भूख नहीं लगना

इस नये वेरियंट में ऐसा नहीं होता है

1. मरीज को अत्यधिक खांसी नहीं होता
2. मरीज को इसके संक्रमण में बुखार नहीं होता
3. नाक और गले के नमूनों से हर बार इसका पता नहीं चलता
4. जिनेम सिक्वेसिंग से फेफड़े में इसके संक्रमण का पता चलता है

बचाव के लिए क्या करना चाहिए

1. फिर से भीड़ वाले इलाकों में मास्क पहनकर चलिए
2. लोगों से कमसे कम डेढ़ मीटर की दूरी बनाकर रहिये
3. हाथों को पहले जैसा नियमित तौर पर साबुन से धोते रहिये



















प्रदर्शन हाईकोर्ट ने चिटफंड घोटाला मामले में सरकार से पूछा

## निवेशकों के डूबे पैसा की वापसी को लेकर कोई कमेटी बनाई है या नहीं?

राष्ट्रीय खबर

रॉची: चिटफंड घोटाला मामले में निवेशकों के डूबे पैसों की वापसी को लेकर दायर नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि निवेशकों के दावों के मद्देनजर उनके पक्ष में पैसा निर्गत करने को लेकर झारखंड में कोई कमेटी बनाई गई है या नहीं। अगर कमेटी बनाई गई है तो इस कमेटी ने अब तक क्या कार्य



किया है। इस पर स्टेट्स रिपोर्ट अगली सुनवाई में दखिल करे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 मई निर्धारित की

है इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चिटफंड घोटाला में शामिल कई कंपनियों के संचालकों की ईडी

और सीबीआई ने करोड़ रुपए की संपत्ति एवं पैसे सीज किए हैं। चिटफंड घोटाला के सीज पैसे ईडी और सीबीआई ने बैंकों में

खी गये हैं। कई राज्यों में एक कमेटी बनाकर चिटफंड के शिकार लोगों के केस को डिस्पोजल किया जा रहा है और उन्हें उनके डूबे पैसे वापस दिलाए जा रहे हैं। झारखंड में भी कमेटी बनाकर निवेशकों के डूबे पैसे को वापस दिलाया जाए। बता दें कि प्रार्थी ने याचिका दखिल कर कहा है कि चिटफंड कंपनियों ने अधिक ब्याज का लालच देकर उनके पैसे का गबन कर लिया है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन निवेशकों के डूबे पैसे भी वापस दिलवाने की पहल की जाए।

व्यापारी कर रहे ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया सरल करने की मांग, किराया दुकानदारों को अधिक परेशानी

राष्ट्रीय खबर

रॉची: ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया सरल करने की मांग लंबे समय से व्यापारी कर रहे हैं। इसके लिये चैबर ऑफ कॉर्म्स की ओर से कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। लेकिन इस पर कोई विशेष पहल नहीं की जा रही है। व्यापारियों की मांगें तो नगर निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस मिलने में काफी परेशानी हो रही है। मामले में कुछ व्यापारियों ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया काफी जटिल है। अधिक कागजातों की मांग की जाती है। लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिये महीनों इंतजार करना पड़ता है। कई मामलों में सभी कागजात उपलब्ध करने के बाद भी विभागीय प्रक्रिया में विलंब के कारण लाइसेंस के कार्य लंबित हो रहे हैं। आवेदन करने के बाद भी महीनों व्यापारियों को लाइसेंस के लिये इंतजार करना पड़ रहा है। किराया में संचालित दुकानदारों को इससे अत्यधिक समस्या हो रही है। ऐसे में व्यापारिक



गतिविधियां बाधित हो रही हैं। हालांकि ऑफ कॉर्म्स की मांगें तो सिर्फ रॉची नगर निगम ही नहीं, अन्य नगर निगम क्षेत्र में भी ट्रेड लाइसेंस और रिन्यूअल को लेकर परेशानी है। लाइसेंस के मामले में लगातार चैबर ऑफ कॉर्म्स अधिकारियों से वार्ता कर रहा है। जहां ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया सरल करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों ट्रेड लाइसेंस की मांग करते हुए व्यापारियों ने नगर आयुक्त शांति रंजन को पत्र सौंपा। जिसमें ट्रेड लाइसेंस से जुड़ी समस्या और इसके समाधान पर चर्चा की गयी। पत्र में बताया गया है कि ट्रेड लाइसेंस की जटिल

प्रक्रियाओं को सरल किया जाना चाहिये। यह सुझाया गया कि निर्धारित शुल्क के साथ एक साधारण आवेदन, जीएसटी निबंधन, आधार, पैन कार्ड लेकर ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने की व्यवस्था की जाये। जीएसटी निबंधन नहीं होने की स्थिति में एफिडेविट या किसी सरकारी दस्तावेज (जैसे बिजली बिल, टेलिफोन बिल इत्यादि) का विकल्प दिया जा सकता है। ऐसा करने से व्यापारियों की समस्या कम होगी। बता दें पिछले कुछ महीनों से लगातार चैबर ऑफ कॉर्म्स ट्रेड लाइसेंस सरलीकरण की मांग उठा रहा है।

## संयुक्त परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा पर चलेगी विभागीय कार्यवाही



राष्ट्रीय खबर

रॉची: संयुक्त परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग प्रदीप कुमार पर विभागीय कार्यवाही चलेगी। उनके उपर प्रखंड विकास पदाधिकारी हिरणपुर, पाकुड़ के पद पर रहते हुए कई गंभीर आरोप लगे थे। झारखंड प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी पर पाकुड़ बीडीओ के पद पर रहते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 में क्रियान्वित तीन योजनाओं को महज तीन वर्ष के अंतराल पर ही अधुरा एवं

विवादित बताते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुनः उसी स्थल पर कृष्ण मड़ैया के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार, दूसरी योजना बलदेव साहा के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार एवं तीसरी योजना देवेन्द्र साहा के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार कार्य करवाने एवं क्रियान्वित योजनाओं में एफटीओ करते हुए राशि का गबन करने में सहयोग करने, अभिकर्ता के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन नहीं करवाने तथा उक्त तीनों योजना में फर्जी मस्टर रोल सहारे

लोकधन का जालफरेबी, धोखाधड़ी एवं कुटकरण के सहारे गबन कराकर बंदरबांट कराने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। पूरे मामले पर प्रमंडलीय आयुक्त दुमका ने सरकार को 2017 में कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया था, जिसकी जांच प्रथमदृष्टया आरोप सही पाये गये। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया और जांच संचालन पदाधिकारी रिटायर आईएस रमाकांत सिंह को नियुक्त किया है। उपस्थान पदाधिकारी के रूप में डीआरडीए पाकुड़ के निदेशक को नामित किया गया है। प्रदीप कुमार वर्तमान में संयुक्त परिवहन आयुक्त रोड सेफ्टी के पद पर कार्यरत हैं। इस संबंध में कार्यात्मक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है।

## फुट ओवर ब्रिज बनाने को एजेंसी की तलाश में लगा जुडको

राष्ट्रीय खबर

रॉची: राज्य सरकार की ओर से मेन रोड स्थित अल्बर्ट एक्का चौक और किशोरगंज चौक पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना है। इसके लिए जुडको (झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड) की ओर से एक बार फिर ई-टेंडर जारी किया गया है। किशोरगंज चौक के लिए तो आठवीं बार निविदा जारी की गई है जबकि अल्बर्ट एक्का चौक के लिए तीसरी बार। जुडको के प्रोजेक्ट डायरेक्टर (टैक्निकल) के मुताबिक दोनों जगहों पर फुट ओवर ब्रिज के साथ-साथ एस्कलेटर्स की भी सुविधा होगी। 8 मई तक दोनों कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अल्बर्ट एक्का चौक पर बनने वाले फुट ओवर ब्रिज के लिए जुडको ने 17.69 रुपये की योजना तय कर रखी है।



इसके लिए आवेदन करने वाले को टेंडर डॉक्यूमेंट के लिए 25 हजार रुपये देने होंगे (नन रिफंडेबल)। बिड सिक्युरिटी मनी के तौर पर 17.69 लाख रुपये लगेगे जो रिफंडेबल होंगे किशोरगंज चौक के फुट ओवर ब्रिज के लिए 460.243 लाख रुपये की योजना है। टेंडर डॉक्यूमेंट के तौर पर 10 हजार रुपये और बिड सिक्युरिटी मनी के तौर पर 4.60 लाख रुपये लगेगे। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट को मदद लेनी होगी। कचहरी चौक, रॉची स्थित जुडको कार्यालय से भी मदद ली जा सकती है।

## तीन सब इंस्पेक्टर समेत 31 जवान पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त



रॉची: लग-अलग जिले में पदस्थापित तीन सब इंस्पेक्टर समेत 31 पुलिसकर्मियों को पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दी है। जारी निर्देश में कहा गया है कि इसे लेकर जिले के एसपी और कमांडेंट को निर्देश दिया गया है कि इन सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को अभिलंब पुलिस मुख्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। इन पुलिसकर्मियों को मुख्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है उनमें सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार रजक, मारुत नंदन, अमित अलेक्जेंडर कुजुर और रोशन कुमार शामिल हैं। इसमें सीमा कुमारी, इकराम उल्लाह मलिक, विजय कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, विकास कुमार, दीपक पुंज, हीरालाल रविदास, जन्मेजय मुंडा, सुखदेव खलखो, गोबाई कुजुर, सुशील कुमार, नागेंद्र कुमार पांडे, अमर कुमार, सिकंदर विजेता, उषेंद्र करमाली, रणधीर कुमार सिंह, संजय कुमार महतो, अरुण कुमार पांडे, देव कुमार सिंह, रिंकू कुमार रजक, अखिल चौरसिया, मनीष कुमार यादव, चंदन कुमार सिंह, लालू कुमार, कमलेश कुमार, कुमार आमप्रकाश और मृत्युंजय कुमार शामिल भी हैं।

## आपत्ति के बाद भी काट दी वेशायर होम रोड की जमीन की रसीद



राष्ट्रीय खबर

रॉची: प्रेम प्रकाश के करीबी पुनीत भार्गव ने राजेश राय से जमीन खरीदने के बाद जिसे बेची उसका म्यूटेशन भी हो गया। गाड़ी मौजा स्थित भूखंड जिसका खाता 37 और प्लॉट नंबर 28 है, उसका म्यूटेशन बड़गाई अंचल कार्यालय से हुआ है। म्यूटेशन के बाद अब पंजी 2 में वर्तमान मालिक (जिसने पुनीत भार्गव से भूमि खरीदी) का नाम दर्ज दिखाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सीओ मनोज कुमार और खतियानी मालिक होने का दावा करने वाले उमेश गोप के

बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में उमेश गोप बड़गाई सीओ से यह पूछ रहे हैं कि उनकी आपत्ति के बावजूद विवादित भूमि का म्यूटेशन क्यों किया गया। इसके जवाब में सीओ मनोज कुमार ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि बार-बार फोन मत कीजिए, अगर आपको गलत लग रहा है, तो आगे बढ़िए। इतना ही नहीं बड़गाई सीओ ने आपत्ति करने वाले व्यक्ति से ये भी कहा कि म्यूटेशन का टाइमल सूट से कोई मतलब नहीं है, नकल लीजिए और आगे बढ़िए।

## तालाब व जलाशय दूषित न हो, ध्यान दे सरकार: हाईकोर्ट

राष्ट्रीय खबर

रॉची: रॉची के विभिन्न जलाशयों और तालाबों के अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने और राज्य सरकार द्वारा दिये गये जवाब के बाद अदालत ने यह याचिका निष्पादित कर दी है। साथ ही अदालत ने प्रार्थी को यह छूट दी है कि अगर निगम और सरकार हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो दोबारा अवमानना याचिका दखिल कर सकती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नदियों और तालाबों के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया है और तालाब प्रदूषित न हो इसके लिए



भी कई कदम उठाए गए हैं। बता दें कि रॉची के बड़ा तालाब और जिला के आसपास के जलस्रोतों को संरक्षित करने और इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। खुशबू कटारुका के द्वारा दखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा

तालाब, किके डैम और धुवा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों द्वारा हड़प ली गई है। वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। जिसका बुरा असर जलाशयों पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं रॉची में तालाबों की स्थिति भी बदतर होती जा रही है।

## तैयारी जेबीवीएनएल गर्मी को देखते हुए अगले तीन वर्षों की योजना बनायेगा झारखंड में बिजली की मांग और आपूर्ति पर तैयार करें रिपोर्ट : एमडी

राष्ट्रीय खबर

रॉची: झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) गर्मी को देखते हुए अगले तीन वर्षों की योजना बनायेगा। यह निर्देश जेबीवीएनएल के एमडी अविनाश कुमार ने सभी जीएम और एसड के साथ हुई बैठक में दिया। बैठक में जेबीवीएनएल के निदेशक केके वर्मा समेत निगम के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। एमडी ने कहा कि गर्मी के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। कभी 2800 मेगावाट तक चली जाती है, तो कभी 2300 मेगावाट पर रहती है। इसलिए सभी जीएम और एसड बिजली की मांग का अध्ययन कर रिपोर्ट बनायें। यह रिपोर्ट सितंबर तक के लिए होगी कि कितने तापमान में कितनी



बिजली की जरूरत पड़ेगी। साथ ही एक रिपोर्ट अगले तीन वर्षों की मांग और आपूर्ति पर हो, ताकि जेबीवीएनएल अतिरिक्त बिजली के लिए पीपीए कर सके। तीन वर्षों में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन

चालू हो जायेगा। तब बिजली की समस्या समाप्त हो जायेगी। एमडी ने कहा कि दिन में कितनी बिजली की खपत होती है, इसके लिए अतिरिक्त बिजली सोलर से लेने के लिए पीपीए किया जायेगा। वहीं

पीक आवर शाम छह बजे से रात 10 बजे के बीच बिजली की मांग के लिए पुष्प पोर्टल की मदद लेने का निर्देश दिया गया है। 10 मार्च को केंद्र सरकार ने सरप्लस बिजली के लिए पुष्प पोर्टल आरंभ

किया है। इससे 12 रुपये प्रति यूनिट से कम दर पर बिजली मिलेगी। 250 से 300 मेगावाट के लिए पीपीए करने की बात हुई। साथ ही 150 मेगावाट बिजली को डिमांड बेस्ड पीपीए करने का निर्देश दिया गया है। एमडी ने सभी जीएम को सितंबर माह तक के लिए प्रत्येक प्रिया बोर्ड में एक कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है। जिसमें बिजली कटते ही लोगों को सूचना दी जायेगी कि किस वजह से बिजली कटी है। कहां भी तकनीकी खामी आने पर तत्काल मरम्मत करने की बात कही गयी। कंट्रोल रूम का नंबर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी एड और जेड को सब स्टेशन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है।

राष्ट्रीय खबर  
हमारी नज़र  
नौ कदम और

dillhi  
तेलेंगना  
हिमाचल प्रदेश  
जम्मू-कश्मीर  
गुवाहाटी  
आंध्रप्रदेश  
चंडीगढ़  
बिहार  
झारखंड

e-mail (bangla) : rashtriyokhobor@gmail.com  
http://rashtriyakhabar.com/epaper  
e-mail : rashtriyakhabarhn@gmail.com  
web : www.rashtriyakhabar.com

Rashtriya khabar  
Rashtriyakhabar LIVE  
jatiyokhobor.co.in

Visit us @Ph.  
0651-2244505  
0651-2244605